व्यापार पेज 2
27.10.13

छोटी दुकानों का विशेष महत्व : वित्त मंत्री के बयान से व्यापारी उत्साहित

रमाकांत चौधरी

नई दिल्ली । पिछले दिनों वाशिंगटन दौरे पर गए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरम द्वारा भारत में वालमार्ट के प्रवेश को कोई विशेष तव्वजो नहीं दिए जाने और यह कहने पर की भारत का बाजार लाखों छोटी दुकानों के बलबूते पर मजबूत है जैसे ब्यान देने से देश भर के व्यापारियों के शीर्ष संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि आखिरकार वित्त मंत्री को देश भर में फैले छोटे व्यापारियों की आवश्यकता और महत्वत्ता की समझ आ ही गई है।

इस बावत कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवान ने एक संयुक्त ब्यान में बताया कि आखिरकार देर से ही सही छोटी दुकानों के महत्वत्ता को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरम ने जिस वास्तविकता के साथ स्वीकार किया है जिसे अब केन्द्र सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए और देश के रिटेल व्यापार को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए जिससे देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि विदेशी कम्पनियों की ओर देखने और उनका मोह केन्द्र सरकार को छोड़ देना चाहिए क्योंकि विदेशी कम्पनियां विशुद्ध रुप से अपने लाभ को पहले

पायदान पर रखती है और उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती से कोई लेना देना नहीं है।

श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा कि निश्चित रुप से देश के रिटेल व्यापार में भारी पैमाने पर सुधार लाने की गुंजाईश है और जिसे आधुनिक बनाने की बेहद आवश्यकता है। बहरहाल जिसके लिए किसी भी प्रकार के विदेशी धन अथवा छोटी दुकानों के स्थान पर बड़े शॉपिंग माल या रिटेल स्टोर की चेन की कतई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कैट ने इस मुद्दे पर शुरु से ही यही कहते आ रहा है कि बड़े विदेशी स्टोरों के स्थान पर देश के वर्तमान व्यापरिक ढांचे को चुस्त- दुरस्त किया जाए लेकिन केन्द्र सरकार ने हमेशा ही विदेशी कम्पनियों का पक्ष लिया और उनके अनुसार नीति बनाई गई जबकि घरेलू व्यापार को सदैव अपेक्षित ही रखा गया।

उन्होंने रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश के मामले पर कैट के विरोध करने के स्टैंड को दोहराते हुए केन्द्र सरकार से मांग की है कि घरेलू व्यापार को उच्च तकनीकी,आधुनिक और वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक सक्षम नीति बनाई जानी चाहिए। जिसके अन्तर्गत व्यापारियों को बैक एण्ड को मजबूत करने,आईटी तकनीक का व्यापारियों द्वारा उपयोग,व्यापारिक ढांचे को ई गर्वेनेंस में ढालना,सरल कर प्रणाली और उपभोक्ता की मजबूती के सिद्धांत को शामिल किया जाए।